

### बिहार सरकार लेकर आई

### सौगातों की बहार

#### जनकल्याण से विकास तक, हर वर्ग के लिए नए अवसर

### 125 यूनिट बिजली नि:शुल्क, मिलेगा सौर ऊर्जा को बढ़ावा

- राज्य के सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली निःशुल्क
- अगले 3 वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों/सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का अधिष्ठापन



#### जनसेवा में जुटे कर्मियों के मानदेय में वृद्धि

- विद्यालय रसोइयों का मानदेय ₹1600 से बढाकर ₹3.300 प्रतिमाह
- किसान सलाहकार का मानदेय ₹13,000 से बढ़ाकर ₹21,000 प्रतिमाह
- स्कूलों के रात्रि प्रहरियों का मानदेय ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रतिमाह
- शारीरिक शिक्षकों व स्वास्थ्य अनुदेशकों को ₹8,000 से बढ़ाकर ₹16,000 प्रतिमाह
- बीएलओ का वार्षिक पारिश्रमिक ₹10,000 से बढाकर ₹14,000
- बीएलओ सुपरवाइजर का वार्षिक पारिश्रमिक ₹15,000 से बढाकर ₹18,000



#### 1 करोड़ से अधिक रोजगार युवा शक्ति को बल

- राज्य सरकार का अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक रोजगार एवं नौकरियां देने का लक्ष्य
- बिहार युवा आयोग के गठन से राज्य के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता
- टीआरई-4 शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लाग्, बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ
- BIADA एमनेस्टी पॉलिसी व बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 से उद्योग विस्तार और रोजगार को मिलेगा बढावा
- सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा शुल्क ₹100 तथा मुख्य परीक्षा निःशुल्क
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को इंटर्नशिप के लिए ₹4,000 से ₹6,000 प्रतिमाह
- दिव्यांगजन के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी एवं यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर क्रमशः ₹50 हजार एवं ₹1 लाख देने का प्रावधान
- गिग कामगारों को दुर्घटना से मृत्यु पर ₹4 लाख, विकलांगता पर ₹2.5 लाख एवं इलाज हेत् ₹16,000 तक की सहायता

### बढ़ी हुई पेंशन से मिला आर्थिक संबल

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (वृद्धजन, विधवा एवं दिव्यांगजन) के अंतर्गत अब ₹400 से बढाकर सीधे मिल रही है ₹1,100 मासिक पेंशन
- लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण



#### हर कंधे को ताकत हर हाथ को सहारा

- निजी बस ऑपरेटरों को नर्ड बस खरीदने पर ₹20 लाख की सब्सिडी
- जीविका 'दीदी की रसोई' में ₹40 की जगह ₹20 में मिलेगी पौष्टिक थाली
- जे.पी. सेनानी पेंशन ₹7,500 से ₹15,000 व ₹15,000 से ₹30,000
- पत्रकारों की पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹15,000 प्रतिमाह
- मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कलाकारों को अब ₹3,000 प्रतिमाह
- मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना के तहत गुरुजी को ₹15,000, संगतकार को ₹7,500 और शिष्य को ₹3,000 प्रतिमाह



#### हर महिला सशक्त, हर परिवार खुशहाल

#### सभी सरकारी नौकरियों में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण

- 1.40 लाख जीविका कर्मियों का मानदेय हुआ दोगुना, साथ ही जीविका दीदियों को ₹3 लाख से अधिक बैंक ऋण 10% ब्याज दर से घटकर 7% पर
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना से सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹50 लाख की राशि स्वीकृत
- आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रतिमाह
- आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल खरीदने के लिए ₹11,000 सहायता
- ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव ₹300 से बढ़ाकर ₹600 की प्रोत्साहन राशि



#### नालंदा विश्वविद्यालय



डा. अमरजीत कुमार शिक्षाविद

ष्टार के राजगीर में स्थित **ा** नालंदा विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के दस वर्ष पुरे कर लिए हैं। एक ओर यह ऐतिहासिक महत्व और अंतरराष्ट्रीय पहचान के कारण चर्चा में है, तो दसरी ओर छात्र संख्या को लेकर गंधीर चुनौतियों से जुझ रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा संसद में उपलब्ध कराए गए आंकडे इस स्थिति की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं। गौरतलब है कि सत्र 2024-25 में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या महज 402 रही। इससे पहले 2023-24 में यह 266 थी। वर्ष 2022-23 में 247. 2021-22 में 240 और 2020-21 में केवल 173 छात्रों का नामांकन हुआ था। हालांकि इसमें विदेशी छात्रों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है. फिर भी ये आंकड़े चिंतनीय हैं। शिक्षा विशेषजों का मानना है कि यदि समय

### पुराना वैभव पाने की कठिन राह

नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों की कम संख्या चिंता का विषय है। पाठ्यक्रमों और शोध गतिविधियों को विस्तार देते हुए यह संस्थान अपनी गरिमा फिर से हासिल कर सकता है

रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय अपनी वैश्विक महत्ता के बावजूद छात्रों को आकर्षित करने में पिछड सकता है।

यह विश्वविद्यालय अनुसंधान-प्रधान अंतरराष्ट्रीय विवि है और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। आज भी प्राचीन गौरव को आधुनिक स्वरूप में पनर्जीवित करने की राह पर है। लगभग 500 एकड में फैला इसका परिसर देश के बड़े परिसरों में शामिल है। यह भारत का पहला विवि है जिसने 'नेट जीरो' इको-रीसाइक्लिंग रणनीति अपनाई है। विवि छह प्रमुख स्कूलों-ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिकी व पर्यावरण अध्ययन, बौद्ध अध्ययन, दर्शन एवं तुलनात्मक धर्म, भाषाएं व साहित्य तथा प्रबंधन अध्ययन में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा, यहां सनातन धर्म अध्ययन तथा संस्कत. पाली, तिब्बती, जापानी और कोरियार्ड भाषाओं में डिप्लोमा पाठयक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

नालंदा विवि को पुनर्जीवित करने के लिए भारत सरकार ने 2010 में अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के बीच क्षमता निर्माण के लिए सहयोग स्थापित करना है। इस अधिनियम में प्राचीन भारतीय विज्ञान, दर्शन, भाषा, इतिहास और अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्रों को पनर्जीवित करने पर बल दिया गया है, जो मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहां हजारों छात्र विश्व के विभिन्न हिस्सों से शिक्षा प्राप्त करने आते थे। इसी परंपरा को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ाना अधिनियम का मूल उद्देश्य है। यही कारण है कि इसे भारत के शैक्षणिक इतिहास में एक पुनर्जागरण का दस्तावेज कहा जा सकता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र : नालंदा विवि की स्थापना की परिकल्पना भारत तथा पूर्वी पशियाई देशों के साझा सहयोग से की गई है, जो क्षेत्रीय स्तर पर ज्ञान और शिक्षा के आदान-प्रदान को पुनः केंद्र में लाने का प्रतीक है।
महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति
(एनईपी) 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा
को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाने पर
विशेष जोर दिया गया है। इस नीति का
उद्देश्य विद्याधियों को न केवल आधुनिक
शिक्षा से जोड़ना है, बल्कि उन्हें अपनी
सांस्कृतिक और बाँद्धिक धरोहर से भी
अवगत कराना है। ऐसे में यदि नालंदा
विश्वविद्यालय पारंपरिक विषयों को
समकालीन शोध और अंतर्विषयी
अध्ययन से जोड़ सके, तो यह भारत की
प्राचीन धरोहर को पुनः विश्व मानचित्र
पर स्थापित करने में भी सक्षम होगा।

बदलता प्रवेश पैटनं और नई चुनौती: आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक विदेशी छात्र स्नातक स्तर पर नामांकित हैं, जिनकी हिस्सेदारी 74.8 प्रतिशत है। स्नातकोत्तर स्तर पर यह संख्या केवल 15.8 प्रतिशत है। इसमें नेफल और अफगानिस्तान के विद्यार्थी सबसे ज्यादा हैं। दसरी



लगभग 500 एकड में बनाया गया है बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का भव्य परिसर

फाइट

ओर. भारतीय छात्रों की पसंद तेजी से बदल रही है। लगभग 70 प्रतिशत धारतीय छात्र विदेश में स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों का चयन कर रहे हैं। वहीं नालंदा विवि में स्नातकोत्तर और शोध का कार्य किया जाता है, जबकि वर्तमान में यह बौद्ध अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन, पारिस्थितिको एवं एवविरण अध्ययन तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों पर केंद्रित है। ऐसे में विद्यार्थियों की बदलती राचियों और रोजगार की मांग को देखते हुए यह जरूरी है कि विवि आधुनिक पाठयक्रम विकसित करे। नालंदा विवि के सामने चुनौती है कि वह अपने उद्देश्यों को परा करते हुए बदलते प्रवेश पैटर्न में छात्रों को आकर्षित करे। नई शिक्षा नीति बहविषयक शिक्षा प्रणाली को

महत्व देती है, जिससे नालंदा पारंपरिक और आधुनिक विषयों के समन्वय से वैश्विक केंद्र बन सकता है।

नालंदा विवि का प्रवेश आंकड़ा चिंता का विषय है, लेकिन यह संस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर और विशेष अधिनियम 2010 के बल पर भविष्य में नई ऊंचाइयां छू सकता है। इसके लिए जरूरी है कि यह संस्थान छात्रों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रमों और शोध गतिविधियों को विस्तार प्रदान करे। यदि नालंदा भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिकता का संगम प्रस्तुत कर सका, तो यह न केवल भारत की प्राचीन गौरवगाथा को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय शिक्षा मानचित्र पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ने में सक्षम होगा।

**औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज•** उद्योग विभाग के पास 14600 एकड़ का लैंड बैंक

## 100 करोड़ निवेश पर ₹1 में 10 एकड़ व 1000 करोड़ पर 25 एकड़ जमीन मिलेगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर पटना

बिहार में उद्योग विभाग के पास 14600 एकड का लैंड बैंक है, जिसपर फैक्टी लगाने की योजना बनाई जा रही है। यदि फैक्ट्री लगती है तो प्रत्यक्ष रूप से 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आजादी के बाद बियाडा के पास सबसे अधिक लैंड बैंक है। अब तक उद्योग विभाग के पास 7700 एकड़ ही जमीन उपलब्ध थी। इसकी वजह से बडी फैक्ट्रियों के मालिक बिहार में यूनिट लगने से बच रहे थे। साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 के तहत 100 करोड़ रुपए निवेश करने वाले को 1 रुपए में 10 एकड तक जमीन दी जाएगी, जबकि 1000 करोड़ रुपए निवेश करने वाले निवेशकों को 25 एकड़ तक जमीन मिलेगी।

टेक्सटाइल और लेदर इकाईयो में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने 5000 रुपए



टेक्सटाइल और लेदर इकाईयो में कार्यरत कर्मचारियों को प्रति महीने 5000 रुपए ईएसआई और ईपीएफ योजना के तहत मिलेगा। ये पैसा 7 वर्ष तक दिया जाएगा। दूसरे उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों को 2 हजार रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। बिहार में यूनिट लगाने वाले निवेशकों को 40 करोड़ रुपए तक ब्याज अनुदान मिलेगा। उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले क्षेत्र की इकाईयों के अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जेडएलडी और सीवेज उपचार संयंत्र (1 करोड रुपए तक) की स्थापना पर खर्च के लागत का 25% सस्कार देगी। इसके साथ ही कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, स्टाम्प इयूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहयोग, पेटेंट पंजीकरण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता दी जाएगी।

कार्यक्रम में ये उपस्थित थे: बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 को लेकर राजधानी के एक होटल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, निदेशक तकनीकी विकास शेखर आनंद मौजूद थे।

₱ देश में पहली बार बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज-2025 शुरू किया गया है। 31 मार्च 2026 तक इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रोत्साहन से 20 लाख करोड़ रुपए निवेश आने की संभावना है।- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री, बिहार

#### कैबिनेट न्यूज॰ कृषि सलाहकारों को अब 21 हजार मानदेय, 3 पनबिजली परियोजनाएं बंद होंगी

## राशन डीलरों का कमीशन 52% बढ़ा

पॉलिटिकलरिपोर्टर पटना

पीडीएस दुकानदारों (जनवितरण प्रणाली के डीलर) का कमीशन 52% बढाया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 50 हजार राशन डीलरों को फायदा होगा। कैबिनेट ने मंगलवार को कमीशन बढ़ाने का निर्णय लिया। अबतक डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में प्रति क्विंटल 45-45 यानी 90 रुपए निर्धारित था। अब सितंबर से प्रभावी करते हुए राज्य योजना से अतिरिक्त 47 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन में वृद्धि का फैसला हुआ है। साथ ही कुल दर केन्द्रीय सहायता. राज्यांश व राज्य योजना मद को मिलाकर 211.40 रुपए से बढ़ाकर 258.40 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं, कृषि सलाहकारों को 13 हजार की जगह 21 हजार रुपए मासिक मानदेव मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 से बढ़ी हुई राशि का भगतान किया जाएगा। यानी बीते एक अप्रैल से 21 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 67.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में इस समय 7047 कृषि सलाहकार काम कर रहे हैं, जिनको इसका सीधा लाभ होगा। उनकी परामर्श अवधि भी एक घंटे बढ़ाई गई है। यह छह की जगह सात घंटे की गई है।

#### राजस्य महाभियान में 11549 सीएससी कर्मियों की सेवा लेने की मंजूरी

कैबिनेट ने सीएससी, ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को गैर-परामर्शी सेवाओं के तहत नामित करने की मंजूरी दे दी है। इससे राजस्व महाभियान के तहत आयोजित शिविरों में सीएससी के प्रशिक्षित कमीं मौजूद रहेंगे। नागरिकों के आवेदन की तत्काल इंट्री सुनिश्चित कमेंगे। सर्वे अमीनों की हड़ताल को देखते हुए महाभियान को सफल करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कुल 38 जिलों के 8481 हलका में सीएससी के 11549 कर्मियों की सेवा ली जाएगी। इनमें 10936 कंप्यूटर ऑपरेटर, अंचल और जिलास्तर पर 537 तथा 76 पर्यवेक्षक होंगे। सीएससी पहले से ही राज्य में जमाबंदी देखने, लगान भुगतान, दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और भू-मापी जैसी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराती रही है।

#### पथ निर्माण के लिए 481.22 करोड़ मंजूर

पथ निर्माण के लिए 381.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पथ प्रमंडल बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान (एसएच-५६) से फुलतोडाघाट पथ की कुल 20.80 किमी लंबाई में व्यापक कार्य की योजना को स्वीकृति मिली है। यह सडक दरभंगा और खगड़िया के बीच सुगम संपर्कता प्रदान करती है। इस पथ के निर्माण से 3-4 घंटे की दरी सिर्फ 50 मिनट में तय होगी। वहीं पटना नहर के बाएं बांध सह सोन सुरक्षा तटबंध को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह काम फरवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

#### दिव्यांग उद्यमियों के लिए नई योजना

राज्य के दिव्यांग युवा एवं युवितयों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए एक नई मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है। यह मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की तर्ज पर लागू होगी। इसके तहत उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें 5 लाख सब्सिडी और 5 लाख लोन पर दिए जाएंगे। इस वर्ष राज्य सरकार ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

#### वैशाली में अब होटल या रिसॉर्ट बनेगा

वैशाली स्थित बुद्ध सम्यक संग्रहालय परिसर में अब रिसॉर्ट या होटल का निर्माण हो सकता है। इसके लिए 10 के स्थान पर 5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। यहां पीपीपी मोड (जन-निजी भागीदारी) से निर्माण कराया जाएगा। उधर, राज्य की तीन निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाएं बरबल, रामपुर और नटवार बंद होंगी। जबकि 9 अन्य बिजलीघरों तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, बलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी के निर्माण पर 167 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

#### अन्य प्रमुख फैसले

- पटना के फुलवारीशरीफ अंचल के जगनपुरा मौजा में राज्य सरकार की 0.0158 एकड़ जमीन को मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए 30 हजार रुपए प्रति डिसमिल की दर से पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
- बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए गठित राज्य कार्य योजना, 2017 लागू की गई है।
- गयाजी में डायल-112 के मिरर साइट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के संचालन के लिए 132 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
- सारण के जलालपुर अंचल में 11 बीघा 4 कड़ा जमीन भूमि डेयरी प्रोजेक्ट प्लांट के लिए हस्तांतरित की गई है।
  गयाजी के नगर अंचल के दुबें मौजा में 15 एकड़ जमीन का खेल मैदान के लिए हस्तांतरण किया गया है।

#### 5 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 से 10 लाख का ट्रिप अराउंड पैकेज मंजूर

पटना| कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया है। इसमें पटना से काठमांडू के लिए 5 लाख, गयाजी से शारजाह, बैंकॉक, कोलंबो व सिंगापुर के लिए 10-10 लाख रुपए का ट्रिप अराउंड पैकेज (वीजीएफ राशि) दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता लेने वाले विमानों की क्षमता कम से कम 150 पैसेंजर को बिठाने की होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही हवाई ईंधन यानी एटीएफ (एयर टर्बाइन पयूल) पर लगने वाले वैट की दर को मात्र 1% किया जा चुका है। यह नई नीति पटना के जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और गयाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से लागू की जा रही है। इस पैकेज के तहत कतर, दुबई जैसे अन्य बड़े शहरों को भी जोड़ने की तैयारी की जा रही है।

## अमेरिकी टैरिफ भारत के लिए सबक, इसने देश को जगाने का काम किया

राजीव कुमार 🏻 जागरण

नई दिल्ली: अमेरिका के 50 प्रतिशत के टैरिफ को भारत ने एक सबक के रूप में लिया है। किसी वस्तु के आयात व निर्यात के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहकर अब पूरी दुनिया में भारत की पैठ बढ़ाने की नीति बनाई जा रही है। इस दिशा में वाणिज्य मंत्रालय युद्ध स्तर पर काम कर रहा है ताकि सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में भारतीय निर्यात को बढ़ाया जा सके। किसी वस्तु के आयात के लिए भी किसी एक देश पर निर्भरता नहीं रहे।

वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर वार्ता को फिर से शुरू करने से पहले 25 प्रतिशत के अतिरिक्त शुल्क को समाप्त करवाना किसी एक देश में नहीं, बल्कि दुनियाभर में निर्यात बढ़ाने को लेकर तैयार की जा रही नीति

व्यापार समझौते पर वार्ता से पहले 25% के अतिरिक्त शुल्क को समाप्त कराना चाहता है भारत



चाहता है। वैसे भारत का तर्क है कि सात अगस्त से लग रहे 25 प्रतिशत के पारस्परिक शुल्क को भी बीटीए पर वार्ता शुरू होने से पहले समाप्त किया जाना चाहिए। 25 अगस्त से दोनों देशों के बीच बीटीए के छठे राउंड की बातचीत शुरू होनी थी, मगर इसे टाल दिया गया था। मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर आधिकारिक वार्ता नहीं हो रही है, लेकिन वर्चुअल तरीके से यह प्रक्रिया जारी है। दोनों देश एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हम वार्ता की फिर से औपचारिक शुरुआत करेंगे।

दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई जा रही निर्यात रणनीति पेज>>3 निर्यातकों को सस्ती दर पर कर्ज देगी सरकार पेज>>10 ट्रंप टैरिफ से लगातार दूसरे दिन लुढ़के भारतीय बाजार पेज>>10

## पीएम जन–धन योजना ने लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट: प्रधानमंत्री जन-धन योजना के 11 साल पूरे होने पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा-'इस योजना ने लोगों को अपना भाग्य खद लिखने की शक्ति दी है। जब अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ा होता है तो पुरा देश एक साथ आगे बढ़ता है। पीएम जन-धन योजना से यही हासिल हुआ। इसने सम्मान बढ़ाया, लोगों को अपना भाग्य खुद लिखने की शक्ति दी।' यह योजना 2014 में आज के ही दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, हर परिवार के लिए कम से कम एक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा,पेंशन जैसी सविधाओं तक पहुंच प्रदान की गई है।

पीएम ने एक अन्य पोस्ट में 'माईगोव' द्वारा किए गए पोस्ट को साझा किया जिसमें बताया गया कि कैसे पीएम जन-धन योजना ने पूरे भारत में जीवन बदल दिया। पोस्ट में कहा गया-'गणित के सूत्र नहीं, बल्कि भारत के विकास के सूत्र। भारत की वित्तीय क्रांति एक विचार से प्रेरित है-नवाचार के माध्यम से समावेशन। अंतिम छोर तक बैंकिंग से पीएम वोले- जव अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ता है तो पूरा देश तरक्की करता है वित्तीय समावेशन
से हर घर में आशा
और हर जीवन में
आत्मविश्वास
आया



नरेन्द्र मोदी।

लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए

45

गए हैं डीबीटी के माध्यम से

94%

त्यस्क आबादी का कम से कम एक खाता जरूर है

लेकर महिला नेतृत्व वाले सशक्तीकरण तक, पारदर्शी डीबीटी हस्तांतरण से शासन में विश्वास तक पीएम जन-धन योजना ने भारत में बैंकिंग, बचत और विकास के तरीके को बदल दिया है।'

माईगोव के एक अन्य पोस्ट में कहा गया-'11 साल पहले पीएम ने भारत से वादा किया था कि कोई गरीब परिवार बैंकिंग की दुनिया से बाहर नहीं रहेगा। **56.16** करोड़ जन-धन खाते खोले जा चुके हैं 13 अगस्त 2025 तक देशभर में

(31.31 करोड़) **55.7%** खाताधारक महिलाएं, 66.7% खाते ग्रामीण

व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं

2,67,756 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जन-धन खातों में जमा रकम

4,768 रुपये हो गई है प्रति खाता औसत जमा राशि। कुल जमा राशि 11 साल में लगभग 12 गुना बढ़ी

जन-धन सिर्फ खातों के बारे में नहीं था, यह एक मां के लिए सम्मान संग बचत करने, किसान को बिचौलियों के बिना मदद प्राप्त करने, ग्रामीण को राष्ट्र के विकास का हिस्सा महसूस करने के लिए द्वार खोलने के बारे में था।' मोदी के दृष्टिकोण ने वित्तीय समावेशन को वास्तविकता में बदला, जिससे हर घर में आशा,हर जीवन में आत्मविश्वास आया।

### जापान और चीन की यात्रा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देगी : मोदी

दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री, शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग

कहा, राष्ट्रपतिशी चिनफिंग और पुतिन से मिलने के लिए उत्सुक हं

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरुवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि जापान और चीन की उनकी यात्रा राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढाएगी। इससे क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति, सरक्षा तथा सतत विकास को आगे बढाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान जापान रवाना होने से पहले दिया। अपनी यात्रा के पहले चरण में मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान जाएंगे। वहां से वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर चीन जाएंगे।

यह प्रधानमंत्री मोदी की आठवीं जापान यात्रा होगी। शुक्रवार को वह 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह किसी सम्मेलन में उनके जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होगी। इससे पहले इसी साल जन में दोनों नेताओं की कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मुलाकात हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली बार मई 2023 में जापान का दौरा किया था। जापान यात्रा को लेकर मोदी ने कहा कि हम अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अगले चरण को आकार देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे. जिसने पिछले 11 वर्षों में लगातार प्रगति की है। पीएम ने कहा कि वह तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पतिन से मिलने के लिए उत्सुक हैं। भारत साझा चुनौतियों

#### अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगी पीएम 🌽 मोदी की जापान- चीन यात्रा

प्र धानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिया के दी बड़ी आर्थिक ताकतों चीन और जापान की यात्रा पर हैं। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के 50 प्रतिशत टैरिफ और रमंबंधों में तनाव के बीच पूरी दुनिया की निगाहें पीएम मोदी इस यात्रा पर हैं। आइये जानते हैं कि पीएम मोदी की दो देशों की इस यात्रा को भारत के हितों और भ-राजनीरितक परिदश्य के लिहाज इतनी प्रमखता क्यों दी जा रही है?

#### मैन्युफैक्चरिंग में उछाल ला सकता है जापानी निवेश



प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले जापान जाएंगे। भारत और जापान के बीच पहले से बेहतर संबंध हैं। जायान भारत के साथ क्वाड का भी सदस्य है। ऐसे समय में जब अमेरिकी टैरिक से भारत को कारोबारी मोर्चे पर नुकसान की आशंका है, पीएम मोदी जापान से मेक इन इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए

सक्रिय सहयोग मांग सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं।



- 100 से अधिक आपसी सहमति पत्र पर हो सकते हैं हस्ताक्षर सरकार और कंपनियों के बीच
- क्रिटकल मिनरल्स और हाई वैल्य मैन्यफैक्चरिंग में जापानी निवेश पर होगी बात
- भारत में रेक्ट अर्थ का बड़ा भंडार होने का है
- रेयर अर्थ निकालने के लिए भारत को है तकनीक की जरूरत
- 68 अरब डालर का निवेश करेगी जापान की कंपनियां भारत में अगले दशक तक
- 8 अरब डालर भारत में निवेश करेगी सजकी मोटर अगले 6 वर्ष में
- 25. 000 भारतीय विशेषज्ञ जापान की वर्कफोर्स में शामिल हुए पिछले पांच वर्ष मे
- 50,000 और भारतीय जापान की वक्रफोर्स में शामिल हो सकते हैं अगले पांच वर्ष में

👅 पीएम की जापान यात्रा कई नई पहलों को शरू करने और रिश्तों को मजबत करने का मौका देगी। इसके अलावा दोनों देशों के नेता 🎙 उभरते अयसरों और चनौतियों के महेनजर सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार करेंगे। -विक्रम मिसरी, विदेश सर्विव, भारत सरकार

#### नए सिरे से बढ़ेगा आग्रसी सहयोग

यात्रा के दसरे चरण में पीएम मोदी शंघाई कोआपरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) के सम्मेलन में हिस्सा लेने वीन जाएंगे। यह सम्मेलन रविवार से शरू हो रहा है। 2020 में गलवान में भारत चीन की सेनाओं के वीच खनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण दौर से

मोदी की सात वर्ष के बाद बीन जा रहे हैं। हालांकि वेशिवक व्यापार व्यवस्था को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टंप के मनमाने



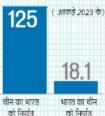
रवैये के महेनज़र दोनों देश रिश्तों को बेहतर बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबुत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मलाकात रिश्तों में सधार की प्रक्रिया को गति दे सकती है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर चीन की ओर से भारत के समर्थन में क्यान आए हैं। ऐसे में मतभेदों के बीच दो वही अर्थव्यवस्थाएं कारोबारी मोर्चे पर सहयोग बदाने के लिए तैयार दिख रही है।

- पांच वर्ष के बाद भारत चीन के बीच शरू हो सकती है सीधी उड़ान
- तीन हिमालयी क्षेत्रों से सीमा त्यापार दोबारा शरू करने पर हो रहा है विचार
- त्यापार बाधाओं को कम करने के लिए काम कर रहे हैं भारत और चीन
- फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनिरल्स के निर्यात पर रोक हटाने पर चीन ने जताई है सहमति
- चीनी कंपनियों के लिए निवेश के नियमों को आसान बनाने पर विचार कर रहा है भारत

🦟 टंप की वजह से वैश्विक व्यवस्था मे अनिश्चितता पैदा हई है। यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि भारत- चीन आपसी सहयोग का ऐसा रास्ता निकाल हो. जो दोनों देशीं के लिए फायदेमंद हो।

-देवाशीष मित्रा, प्रोफेसर, इकनोमिक्स, सिरावयुज यूनीवर्सिटी, न्यूयार्क

#### चीन-भारत द्विवपक्षीय व्यापार (अख डालर)



त्यापार घाटा

- चीन से प्रमुख निर्यात: इलेटानिक्स और मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, मेटल्स, प्लास्टिक और रवर,
- भारत से प्रमख निर्यात: मिनरल और आयल, केमिकल प्रोडक्ट. इलेक्ट्रानिक्स और मशीनरी, मेटल्स, मछली

जागरण रिसर्च

का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग

को प्रगाद करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ काम करने के लिए प्रतिबंद है।

#### पुतिन से 45 मिनट तो चिनिफिंग से 40 मिनट होगी मोदी की मुलाकात

#### भारत व चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं

प्रथम पुष्ट से आगे

भारतीय पक्ष मान रहा है कि भारत-चीन ग्राथ भिलंकर वैधिवक अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सकते हैं। दोनों देशों का सहयोग टंप की शल्क नीति से वैश्विक विकास दर पर नकरात्मक असर को कम कर सकता है। इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा। भारत यह भी मान रहा है खास तौर पर तब जब भारत के लिए विश्वास को और बढाएगा।

पारंपरिक तौर पर आकर्षक अमेरिका व पश्चिमी देशों में बाजार की स्थिति अनिश्चित है। सत्रों के मताबिक. युक्रेन-रूस युद्ध के बाद जिस तरह से वैश्विक बदलाव हम देख रहे हैं उससे हमें बहुधुन्नीय विश्व बनाने की दिशा में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। ऐसे में मोदी-चिनिक्रंग की मलाकात में कारोबारी बाधाएं दर कर चीनी बाजार में भारतीय उत्पादों के कि चीन दनिया की दसरी सबसे बड़ी प्रवेश को आसान करने, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था होने की वजह से मौजदा जनता के बीच संपर्क बढ़ाने का मदा माहौल में भारत की विकास दर की अहम रहेगा। उम्मीद है कि इन मुद्दों आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। पर चीन सकारात्मक कदम उठाकर

जागरण ब्युरो, नई दिल्ली

अमेरिका का दबाव है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे और चीन को लेकर कड़ा रवैया दिखाए। जापान व चीन की यात्रा पर गुरुवार (28 अगस्त) रात रवाना हुए पीएम नरेन्द्र मोदी का जो कार्यक्रम है. वह फिर स्पष्ट करता है कि उक्त दोनों दबावों को भारत ने दरकित्रए कर दिया है। अभी तक जो सचना मिली है, उसके मताबिक एससीओ सम्मेलन की व्यस्तता के बावजद राष्ट्रपति शी चिनर्फिंग के साथ मोर्ज की 40 मिनट और पतिन के बीच मलाकात के लिए 45 मिनट अमेरिका के संबंध बहत असहज हैं। एजेंडा बहत व्यापक है। इस मलाकात का टैरिफ लगा चकी है, जो किसी भी



अमेरिका को संकेत-अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से कोई समझौता नहीं करेगा भारत

आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में जुटी है भारत और चीन की सरकारें



श्री विनक्तिंग ।

तौर पर टेख रहे हैं कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर समझौता नहीं करेगा।

मोदी की दो दिनों के अंतराल में पहले चिनिर्फिंग और बाद में पतिन से भेंट पैसे समय होने जा रही है, जब भारत और

और चीन की सरकारें आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश में जटी हैं। एक वर्ष के भीतर मोदी-चिनिफेंग की यह दसरी मलाकात होगी। वर्ष 2019 में चेन्नई में अनीपचारिक भेंट के बाद मोदी-चिनर्फिंग अक्टबर, 2024 में कर समय तय हुआ है। दोनों बैठकों का ट्रंप सरकार भारतीय अयात पर 50 % कजान (रूस) में मिले थे। उसके बाद सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आएंगे। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर दोनों देशों के को कई रणनीतिकार भारत की तरफ से देश पर अमेरिका द्वारा लगाया जाने वाला विदेश मंत्रियों के बीच तीन और विशेष में होने वाली मलाकात को लेकर दोनों टॅप प्रशासन को यह होस संकेत देने के सबसे ज्यादा शुल्क है। दूसरी तरफ भारत प्रतिनिधियों के बीच दो बैठकें हो चुकी तरफ से जबरदस्त तैयारी चल रही है।

हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से शल्क लगाए जाने के तरीके न सिर्फ कड़ी निंदा की है, बल्कि भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने की बात भी

इसी तरह से मोदी और पतिन के बीच 45 मिनट की मुलाकात को भी काफी महत्वपर्ण माना जा रहा है। अगस्त माह में प्रनुपस्प अजीत होभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग मास्को की यात्रा की थी। इन दोनों की राष्ट्रपति पतिन से मलाकत हुई थी। पतिन इस साल के अंत तक भारत भी आने वाले हैं। वह भारत-रूस शिखर इसके बावजद मोदी और पतिन की चीन

## रेहड़ी–पटरीवालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना में 7,332 करोड़ का प्रविधान

नई दिल्ली, प्रेट्र: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरीवालों की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के पुनर्गठन और इसे 31 मार्च, 2030 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसमें कुल व्यय 7,332 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें 1.15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवाओं के विभाग (डीएफएस) की होगी, जिसमें डीएफएस बैंकों, वित्तीय संस्थानों व उनके ग्राउंड-लेवल कार्यकर्ताओं के जरिये क्रेडिट कार्ड तक पहुंच सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया।

आधिकारिक बयान में कहा गया है

 कैविनेट वैठक में योजना के पुनर्गठन व 2030 तक विस्तार को मंजूरी

कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुगम वनाएंगे

कि पहले किस्त की ऋण सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। दूसरी किस्त की सीमा 20,000 से 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरी किस्त 50,000 रुपये पर बनी रहेगी। जो रेहड़ी-पटरीवाले समय पर दूसरी किस्त का ऋण चुकाएंगे, उन्हें आपातकालीन व्यवसाय व व्यक्तिगत जरूरतों के लिए यूपीआइ से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता मिलेगी। खुदरा और थोक लेनदेन पर डिजिटल भुगतान करने वाले रेहड़ी-पटरीवालों को 1,600 रुपये तक के प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। पहले 31

दिसंबर, 2024 तक मान्य रहने वाली पुनर्गठित योजना का उद्देश्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है।

पीएम स्विनिधि योजना के तहत 30 जुलाई तक 96 लाख से अधिक ऋण, जिनकी कुल राशि 13,797 करोड़ रुपये है, 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरीवालों को वितरित किए जा चुके हैं। बयान में कहा गया है कि योजना का विस्तार रेहड़ी-पटरी वालों के समग्र विकास की दुष्टि से किया गया है। इससे व्यवसाय विस्तार के लिए वित्त का एक विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराया जा सके और सतत विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें। यह न सिर्फ रेहड़ी-पटरीवालों को सशक्त बनाएगा,बल्कि समावेशी आर्थिक विकास, रेहड़ी-पटरीवालों और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक उत्थान, उनकी आजीविका बढाने में मदद करेगा।

### 2038 तक भारत वन जाएगा दूसरी वड़ी अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली, प्रेट्ट: क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में भारत की इकोनमी 2030 तक 20.7 टिलियन डालर तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं 2038 तक भारत के आर्थिकी के 34.2 ट्रिलियन डालर के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है।

ईवाई की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत उचित कदम उठाता है तो वह उच्च अमेरिकी टैरिफ के असर को जीडीपी के लगभग 0.1 प्रतिशत तक कम कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की 6.5 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि दर में अधिकतम 10 आधार अंकों की कमी आएगी। पीपीपी अंतरराष्टीय विनिमय का एक सिद्धांत है। इसका अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में मौजूद अंतर से लिया जाता है। इतना ही नहीं इसके माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता

- ईवाई के मुताबिक, पीपीपी के आधार पर उस समय तक भारत की आर्थिकी 34.2 ट्रिलियन डालर होगी
- अगर भारत ने टैरिफ के खिलाफ मजबूत कदम उढाए तो जीडीपी पर पडेगा सिर्फ 0.1 प्रतिशत का असर



#### आइएमएफ के अनुसार, भारत पहले ही तीसरे स्थान पर

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने वित्त वर्ष 2024-25 में पीपीपी के आधार पर भारत की जीडीपी 14.2 द्रिलियन डालर होने का अनुमान लगाया है, जो बाजार विनिमय दर के संदर्भ में मापे जाने से लगभग 3.6 गुना अधिक है। इस प्रकार, भारत पहले से ही चीन और अमेरिका के

बाद तीसरी सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। अगर भारत और अमेरिका 2028-2030 के दौरान (आइएमएफ के पूर्वानुमानों के अनुसार) क्रमश: 6.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ते हैं तो भारत 2038 तक पीपीपी के संदर्भ में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड सकता है।

महत्वपूर्ण तकनीकों में लचीलापन और उन्नत क्षमताओं का निर्माण करके भारत 2047 तक अपनी विकसित भारत की आकांक्षाओं के और करीब पहुंचने की स्थिति में है। -डीके श्रीवास्तव, मुख्य नीति सलाहकार, ईवाई इंडिया

लगाया जा सकता है। क्रय शक्ति समता के माध्यम से यह भी पता लगाया जाता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रयशक्ति में कितना अंतर या फिर समता मौजुद है।

ईवाई इकोनमी वाच के अगस्त, 2025 अंक में कहा गया है कि भारत दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे गतिशील इकोनमी के तौर पर उभर

रहा है। इसकी वजह मजबूत आर्थिक बुनियादी ढांचा (उच्च बचत और निवेश दरें), अनुकूल जनसांख्यिकी और एक स्थायी राजकोषीय स्थिति है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ दबाव और धीमे व्यापार जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का लचीलापन घरेलू मांग पर उसकी निर्भरता और आधुनिक तकनीकों में बढ़ती क्षमताओं से

उपजा है। रिपोर्ट में अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में पांच सबसे बडी अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक आर्थिक स्वरूप का परीक्षण करती है।



 अप्रता विजनेस से जुड़ी खबरों
 अगर अपडेट के लिए
 स्केन करें या विजिट
 करें jagran.com करें jagran.com



### डा. मोनिका राज

3 तरराष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी एक देश के कदम से विश्व संतुलन की दिशा बदल जाती है। भारत, जिसकी कूटनीति सदैव आत्मसम्मान और संतलन पर आधारित रही हैं. किसी भी देश के आगे झकने वाली नहीं है। यही कारण हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने अपनी ''टैरिफ आक्रामकता'' दिखाते हए भारत पर व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की, तो नई दिल्ली ने इसे झककर स्वीकार करने के बजाय एक संशक्त और स्वतंत्र नीति अपनाई। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल एकतरफा शर्तों पर चलने वाला देश नहीं है। जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर भारत के हितों को आधात पहुंचाने की कोशिश की, तब भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को और गहराई दी। विदेश मंत्री डा. एस जवशंकर की मास्को यात्रा, रूस द्वारा भारत को दिया गया ठोस समर्थन तथा इस वर्ष राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा, ये सभी घटनाएं इस बात के संकेतक हैं कि भारत-रूस रिश्ते नए आयाम प्राप्त कर रहे हैं। यह परिदश्य केवल दो देशों के द्रिपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है. बल्कि यह वैश्विक राजनीति में बटलते समीकरणों का भी प्रतीक है। भारत ने यह दिखाया है कि उसकी विरेश नीति किसी दबाव या धमकी के अधीन नहीं चलती. बल्कि उसके अपने राष्ट्रीय हित और आत्मनिर्णंब उसकी दिशा तब करते हैं। यही "नया भारत" है, जो विश्व मंच पर बराबरी से संवाद करता है और अपनी कटनीति को किसी भी ब्राहरी दबाव में आने से इन्कार करता है।

सोवियत दौर से आज तक : भारत और रूस का संबंध केवल कुटनीतिक औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा है। 1960 से 1970 में जब भारत ने गटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया था. तब भी वास्तविकता यह थी कि उसका झकाव तत्कालीन सोवियत संघ की और अधिक था। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच हुए शांति. मैत्री और सहयोग संधि ने इस रिश्ते की निर्णायक मोड दिया। बांग्लादेश मक्ति संग्राम के समय सोवियत संघ ने भारत का जिस तरह साथ दिया. उसने इस दोस्ती को और मजबत किया। सोवियत संघ के विघटन (1991) के बाद हालांकि भारत-रूस संबंधों में कछ ठहराव आया और भारत ने अमेरिका एवं पश्चिमी देशों की और ज्यादा रुख किया, लेकिन रक्षा

### बदलते दौर में भारत-रूस संबंध

बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में अमेरिका, रूस और चीन अपने-अपने हित साध रहे हैं।ऐसी स्थिति में भारत को रूस के साथ मित्रता. अमेरिका के साथ साझेदारी और चीन के साथ सावधानी की त्रिस्तरीय नीति अपनानी चाहिए।यही संतुलित दृष्टिकोण भारत को न केवल अपनी आर्थिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि वैशिवक मंच पर उसे एक जिम्मेदार, स्वतंत्र और निर्णायक शक्ति के रूप में भी स्थापित करेगा

और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रूस भारत का सबसे भरोसेमंद साझेदार बना रहा। आज जब वैश्विक राजनीति एक नए ध्रवीकरण की और बढ़ रही है. तो भारत-रूस संबंधों की ऐतिहासिक जहें फिर से नई ऊर्जा प्राप्त कर रही हैं।

आज की परिस्थितियों में भारत-रूप संबंधों का सबसे अहम आयाम ऊर्जा क्षेत्र है। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए. तो भारत ने सस्ते दायों पर रूसी तेल खरीदकर न केवल अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पुरी कीं, बल्कि इसे परिष्कृत कर यूरोप को भी आपूर्ति की। इस कदम से भारत ने अपनी आर्थिक कटनीति का परिचय दिया। अमेरिका ने जहां इस पर सवाल उठाए, वहीं यरोप भारत की इस भूमिका से लाभान्वित हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत का ब्यापारिक निर्णय केवल अपने राष्ट्रीय हितों से संचालित होता है. किसी तीसरे देश के दबाव से नहीं। भारत-रूस रक्षा संबंध दशकों पुराने और गहरे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सुखोई और मिग विमानों तक, भारत की रक्षा क्षमताओं में रूस का योगदान अमल्य रहा है। एस-400 मिसाइल डिफेस सिस्टम की ऑपर्ति इसका ताजा उदाहरण है। रूस न केवल हथियार बेचता है, बल्कि भारत के साथ संयक्त उत्पादन और तकनीकी साझेदारी भी करता है। यह सहयोग भारत अग्रसर करने में सहायक है।

और रूस दोनों ही ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और अन्य बहुपक्षीय नीतियों ने इन बहपशीय मंचों को और यह त्रिस्तरीय नीति भारत की कटनीतिक

इन मंचों पर न केवल पश्चिमी वर्चस्व को संतुलित कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउध) की आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। भारत-रूस संबंधों की यंजबती का एक जटिल पहल चीन भी है। ओज रूस और चीन के बीच संबंध प्रगाद हैं। ऊर्जा, व्यापार और सामरिक साझेदारी में मास्को का बीजिंग की और झकाव स्पष्ट है। धारत के लिए यह चनौती है कि वह रूस के साथ अपने रिश्तों को चीन-रूस समीकरण से स्वतंत्र बनाए रखे। सीमा विवाद और इंडी-पैसिफिक क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षा को देखते हुए भारत रूस से ऐसी कटनीति की अपेक्षा करता है. जो उसके हितों को भी सरक्षित रखे। भारत के लिए एक चनौती यह भी है कि अमेरिका से बढते मतभेद कहीं यरोप और ब्रिटेन के साथ उसके संबंधों पर असर न डालें। हाल में भारत और ब्रिटेन के बीच मक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और बरोपीय संघ से भी वार्ता जारी है। भारत को अपनी कटनीति में यह संतलन बनाए रखना होगा कि वह रूस से संबंधों को गहरा करे. साथ ही अमेरिका और यरोप के साथ आर्थिक साझेदारी भी जारी रखे।

श्रासंग्रिक बना दिया है। भारत और रूप

संतलन और संभावनायं : भारत के सामने आज चनौती अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना है। बदलते को आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग की ओर अंतरराष्ट्रीय समीकरणों में अमेरिका. रूस और चीन तीनों ही महाशक्तियां वैश्विक मंचों पर सहयोग : भारत अपने-अपने हित साध रही हैं। ऐसे में भारत को इस त्रिकोणीय दबाव के बीच संतलन साधते हुए आगे बढना होगा। मंचों पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। रूस के साथ मित्रता, अमेरिका के साथ टंप की एकतरफा और अल्पदिष्ट वाली साझेटारी और चीन के साथ सावधानी



#### भारत के लिए रूस और अमेरिका, दोनों जरूरी

से संतुलन की नीति अपनाता रहा है। अत्यंत महत्वपर्ण साबित हुआ है। प्रतिशत से अधिक रक्षा जरूरतें रूस

शीत यद के समय से ही रूस (तब का दसरी और अमेरिका के साथ भारत अवसर अपने हितों के अनुसार सहयोग सोवियत संघ) भारत का सबसे करीबी के सेबंधों की नींव आर्थिक, तकनीकी की शर्ते तय करता है। रक्षा सौदों ये मित्र रहा। रक्षा उपकरणों से लेकर और कटनीतिक आधार पर मजबूत तकनीकी हस्तांतरण का अभाव और ऊर्जा जरूरतों तक रूस ने हर कठिन हो रही है। अमेरिका भारत का सबसे परिस्थिति में भारत का साथ निभावा। बहा व्यापारिक साझेदार है। आइटी, रिश्तों की कमजोर कही है। भारत के वहीं बीते तीन दशकों में अमेरिका के शिक्षा, अनुसंधान, रक्षा तकनीक और लिए आदर्श स्थिति यही है कि वह रूस साथ भारत की निकटता भी लगातार स्टार्टअप के क्षेत्र में अमेरिका भारत के और अमेरिका, दोनों के साथ संतुलन बढ़ी हैं। आर्थिक सहयोग, तकनीकी लिए अवसरों का भंडार लेकर आता बनाकर चले। रूस की ऊर्जा और साझेदारी, शिक्षा, अनुसंधान और है। 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप रक्षा क्षमताएं भारत के लिए अनिवार्य रणनीतिक दिए से अमेरिका भारत का इंडिया' जैसे अभियानों को अमेरिका हैं, वहीं अमेरिका की तकनीकी और अहम सहयोगी बनकर उभरा है। ऐसे में की कंपनियाँ और निवेशकों ने विशेष आर्थिक शक्ति भारत को भविष्य की यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आने वाले बल दिया है। इसके साथ ही भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था का अगुआ बन्ह समय में भारत के लिए किसका साथ प्रवासी समदाय अमेरिका में बड़ी संख्या सकती है। एकपक्षीय सहयोग भारत के ज्यादा फायदेमंद होगा- रूस का या में बस चका है. जो दोनों देशों के रिश्तों हित में नहीं होगा. बल्कि बहस्तरीय अमेरिका का? रूस के साथ भारत के को और गहरा करता है। अमेरिका के सहयोग ही भारत को वास्तविक शक्ति संबंध ऐतिहासिक और भरोसेमंद माने साथ साझेदारी का सबसे बढ़ा लाभ यह देगा। यही कारण है कि भारत को जाते हैं। रक्षा सौदों का अधिकांश हिस्सा है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी ''रणनीतिक स्वायत्तता'' की नीति पर

से पूरी होती हैं। इसके अलावा ऊर्जा में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रूस जा सकता है कि भारत के लिए रूस सरक्षा के क्षेत्र में रूस भारत के लिए पर अत्यधिक निर्धरता भारत को और अमेरिका दोनों ही अनिवार्य हैं। महत्वपूर्ण है। हाल में जब पश्चिमी देशों अंतरराष्ट्रीय दबावों के बीच मश्किल रूस की विश्वसनीयता और अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब स्थिति में डाल सकती है। युक्रेन युद्ध की आधुनिकता, दोनों का संतुलित रूस ने भारत को कच्चा तेल रियायती के बाद से पश्चिमी देशों और अमेरिका संगम भारत को 21वीं सदी में एक टरों पर उपलब्ध कराया। इसका सीधा ने रूस के खिलाफ कठोर रुख अपनाया सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। लाभ भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला है। ऐसे में रूस के साथ ज्यादा नजदीकी इस संतुलन से ही भारत अपनी ऊर्जा और महंगाई पर भी नियंत्रण हुआ। ऐसे भारत को कटनीतिक संतलन बिगाडने समय में जब वैश्विक बाजार अस्थिर की ओर ले जा सकती है। दसरी ओर.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत हमेशा है. रूस का यह सहयोग भारत के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी कभी-कभी दबावपर्ण भी हो जाती है। अमेरिका वीजा नीतियों में सस्ती भारत-अमेरिका अब भी रूस से आता है। भारत की 60 स्थिति को और सुदृह कर सकता है। कायम रहते हुए दोनों महाशक्तियों से हालांकि दोनों देशों के साथ संबंधों समान रूप से संबंध निभाने होंगे। कहा सरक्षा. आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतत्व की राह पर आगे बढ़ पाएगा।

परिपक्क्त और विवेक की असली परीक्षा आवश्यकताओं को परा करने में मटट के रूप में भी स्थापित करेगा। भारत-रूस है। यही संतलित दृष्टिकोण भारत को करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उसे १क संबंध इस यात्रा के अहम आधार स्तंभ ्न केवल अपनी आर्थिक और सरक्षा *जिम्मेदार स्वतंत्र औ*र निर्णायक शक्ति हैं. जो समय के साथ और सशक्त होंगे।

## प्रशांत क्षेत्र में फिजी के साथ रक्षा कार्ययोजना पर काम कर रहा भारत

नया रोडमैप 🕨 फिजी के पीएम राबुका से वार्ता में पीएम मोदी की घोषणा, कई समझौते

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत और फिजी के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर सहमित बनी है। यहां सोमवार को पीएम नरेन्द्र मोदी और फिजी के पीएम सितीवेनी राबुका के बीच चली बैठक में यह फैसला हुआ कि रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर एक रोडमैप बनाया जाएगा। कई समझौतों पर दस्तखत के साथ ही यह पहला मौका है कि भारत ने प्रशांत क्षेत्र के किसी द्वीप देश के साथ रक्षा संबंधों को लेकर कार्य योजना बनाने का फैसला किया है। वैश्विक परिदृश्य में प्रशांत क्षेत्र के छोटे-छोटे द्वीपों के बढ़ते महत्व को देखते हुए भारत सरकार लगातार इनके साथ संपर्क को मजबूत करने में जुटी है। वर्ष 2014 में पीएम बनने के कुछ ही महीनों बाद मोदी फिजी गए थे जबकि वर्ष 2023 में वह पापुआ न्यूगिनी गए थे।

पीएम राबुका से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने साझा प्रेस कानफ्रेंस में कहा, 'हमने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक कार्य



नई दिल्ली में सोमवार को फिजी के अपने समकक्ष सितीवेनी राबुका से मुलाकात करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ।

योजना तैयार की गई है। फिजी की समुद्री सुरक्षा को सशक्त करने के लिए भारत प्रशिक्षण और उपकरणों में सहयोग देगा।' उन्होंने साइबर सुरक्षा और डाटा संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अनुभव साझा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए हाल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी।

दोनों नेताओं की अगुवाई में इसके पहले प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने, समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में भारत-फिजी साझेदारी को और गहरा करने पर व्यापक चर्चा की।

भारत ने 2025 में फिजी में एक भारतीय नौसेना जहाज के पोर्ट काल की घोषणा की, जो समुद्री सहयोग और

वैठक में समुद्री सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर चर्चा

भारत और फिजी के बीच भले ही महासागरों की दूरी हो, लेकिन हमारी आकांक्षाएं एक ही नाव पर सवार हैं।

-नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री

अंतरसंचालनीयता को बढाएगा। फिजी की विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राबुका ने भारत की सहायता का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय की सचिव (दक्षिण) नीना मल्होत्रा ने बताया, 'फिजी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मुल्यवान साझेदार है और प्रशांत क्षेत्र में एक क्षेत्रीय केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।' पीएम मोदी ने फिजी के लिए कई स्वास्थ्य पहल की घोषणा की, जिसमें सुवा में 100 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, डायलिसिस यूनिट, समुद्री एम्बुलेंस और जन औषधि केंद्र शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच छोटे व मझोले उद्योगों, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर बात हुई है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिनमें नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच सहयोग संबंधी समझौता महत्वपूर्ण है। भारतीय मानक ब्यूरो और फिजी के राष्टीय व्यापार मापन विभाग के बीच मानकीकरण और जन औषधि योजना के तहत दवाओं की आपर्ति शामिल को लेकर भी समझौता हुआ है।

### U.S. official calls conflict in Ukraine 'Modi's war'

Trump Trade Advisor accuses Indian offficials of 'arrogance' and 'profiteering' from refining

Democrats slam Trump govt. for extra 25% sanctions on India, noting that the Chinese buy more Russian oil be solved at highest levels, possibly through talks

I thought India could be one

of the earlier deals and they

kind of tapped us along in terms of

the negotiations. Then there is also

aspect of Russian crude purchases

which they've been profiteering on

SCOTT BESSENT

U.S. Treasury Secretary

Everybody in the U.S. loses

because of what India is

doing. The taxpayers lose because

we've got to fund Modi's war

PETER NAVARRO

Former officials express hope that situation will

Suhasini Haidar

NEW DELHI

day after the U.S. imposed 25% secondary sanctions on Indian goods as a penalty for India's purchases of Russian oil, in addition to the earlier 25% reciprocal tariffs, the Trump administration kept up its tirade, terming the conflict in Ukraine "Modi's war".

The U.S. Opposition Democratic party, however, criticised the move, saying that "singling out India" would hurt the U.S. as well. Former U.S. officials, including former Ambassador Kenneth Juster, expressed hope that the situation would be resolved at the highest levels, potentially through a meeting between U.S. President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi.

"India can get 25% off

the tariffs right now if they agree to stop buying [Russian) oil and feeding the war machine," said Mr. Trump's Trade Advisor Peter Navarro, who has been leading the charge on tariffs. He accused Indian negotiators of falsely claiming that India does not charge high tariffs, and of "arrogance" in refusing to cut oil imports from Russia, while "profiteering" from refining Russian oil in partnership with Russian refiners. a reference to the Vadinar refinery in Gujarat.

#### America's cost

"Everybody in America loses because of what India is doing. Consumers and businesses lose, workers lose because India's high tariffs cost us jobs, income and higher raises. The taxpayers lose because we've got to fund Modi's war." Mr. Navarro told the

Bloomberg news agency, accusing India of "getting in bed with the authoritarians" like Russia and China.

U.S. Treasury Secretary Scott Bessent called India-U.S. ties a "complicated relationship", despite good ties between Mr. Trump and Mr. Modi, and said that

the issue was not just Russian oil purchases but India's failure to make a deal with the U.S. on trade.

"I thought India could be one of the earlier deals and they kind of tapped us along in terms of the negotiations. Then there is also the aspect of the Russian crude purchases which

#### Removal of tariffs not a prerequisite for trade talks'

#### NEW DELHI

The removal of the additional 25% tariff on India is not a prerequisite for trade negotiations to resume between India and the United States, but a trade deal would not "be practical" if these tariffs were to remain. according to government sources, to PAGE 12

they've been profiteering on." Mr. Bessent said on Wednesday, where he said the Indian rupee is at "an all-time low" due to recent developments.

Democratic lawmakers. however, attacked the Trump government, pointing out that China buys more Russian oil than India. In the past month, China has increased its intake of Russian oil even as India decreased its purchases.

"Instead of imposing sanctions on China or others purchasing larger amounts of Russian oil, Trump's singling out India with tariffs, hurting Americans and sabotaging the U.S.-India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all," the Democrats in the House Foreign Affairs Committee said on X.

Meanwhile, a number of former U.S. officials who have dealt with India in the past expressed their disappointment with the situation leading to the U.S. slapping 50% tariffs on Indian goods from August 27.

"Unfortunately, the United States and India have managed to convert what appeared to be a true and unprecedented win-win on

trade into a remarkable lose-lose," said Mark Linscott, former U.S. trade negotiator, calling for "cooler heads who understand the value of the relationship" to prevail.

Mr. Juster, also a former U.S. Commerce official who served as Ambassador to India during the first Trump term, told the Council for Foreign Relations that Mr. Trump believes the U.S.-India economic relationship has been "out of balance" for many years. "[Mr.] Modi needed to respond firmly to the new tariffs. But he should also be careful not to paint himself into a corner and to remain open to discussing ways to resolve the trade dispute," he said, expressing the hope that the leaders would meet on the sidelines of the UN General Assembly (UNGA) in September.

### Security agreement, business pacts, bullet train ride on PM's Japan agenda

#### Suhasini Haidar

NEW DELHI

Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart, Shigeru Ishiba, will travel together on a bullet train during his twoday visit to Japan from Friday.

In a statement shortly before leaving for Tokyo on Thursday night, Mr. Modi said the visit would "expand the scope and ambition" of economic and investment ties, and "advance cooperation in new and emerging technologies, including AI and Semiconductors".

During the visit, the two Prime Ministers will hold the much-delayed 15th annual summit, and are expected to upgrade the 2008 Declaration on Security Cooperation, including defence hardware purlaunch chases. "Economic Security" initiative to build resilient supply chains in areas such as critical minerals and artificial intelligence, and increase Japan's investment



In schedule: During his visit, Narendra Modi will travel by a bullet train to Sendai with Shigeru Ishiba. FILE PHOTO

targets to about \$68 billion.

They will also discuss the India-Japan Indo-Pacific plans for the Quad summit due to be held in India, in the face of growing India-U.S. tensions.

The leaders will attend a business event on the sidelines of the visit, and officials estimate that nearly 100 business-to-business (B2B) agreements are likely to be signed. While bilateral trade between India and Japan is relatively low at about \$22.8 billion, Japan is India's fifth-largest source of foreign direct investment, with \$43.2 billion cumulative investment up to December 2024.

The two sides are also expected to discuss Mr. Modi's travel from Japan to China to attend the SCO Summit, where he will hold talks with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin.

#### Meeting with diaspora

Mr. Modi will arrive in Tokyo on Friday morning. Mr Modi is also expected to meet with some members of the Indian diaspora that number about 54,000 across the country.

At the India-Japan Summit, the two sides will release a joint statement as well as the 2035 Vision Statement to upgrade the 2025 Vision Statement announced by Mr. Modi and then Prime Minister Shinzo Abe a decade ago.

On Saturday, Mr. Modi and Mr. Ishiba will travel by the Shinkansen High Speed Rail Network, or bullet train, to Sendai in Mivagi Prefecture, recreating a ride Mr. Modi took with Abe in 2016. They will visit a semiconductor factory and inspect the Tohoku Shinkansen factory of the East Japan Railway Company, officials said. They will discuss the next steps in the 508-km Mumbai-Ahmedabad Shinkansen project, launched in 2017 with Japanese funding. Japan has been India's largest overseas development aid donor since 1958. and the Shinkansen project, originally billed at \$17 billion, is a major venture for both countries.

### Building health for 1.4 billion Indians

ndia's health-care system stands at a defining juncture. The task is dual: expand access for the millions who are underserved, while ensuring affordability amid rising costs. This needs an integrated framework, strengthening insurance, leveraging scale, embedding prevention in primary care, accelerating digital adoption, enabling regulatory clarity, and unlocking sustained investment. Through a systemic, interconnected approach, India can build a health-care model that is inclusive, financially viable, and globally aspirational.

#### Insurance as the foundation of affordability

Pooling risk remains the most effective way to make costly care accessible. Even modest premiums − ₹5,000 to ₹20,000 for individuals or ₹10,000 to ₹50,000 for families − can unlock coverage worth several lakhs, shielding households from catastrophic financial shocks. Yet, penetration remains low: only 15%-18% of Indians are insured, with the premium-to-GDP ratio at 3.7% compared to the global average of 7%. The gap is significant, but so is the opportunity, as gross written premiums already stand at \$15 billion in 2024 and are projected to grow at over 20% CAGR till 2030.

Affordability cannot rest on insurance alone. True impact comes when payers, providers and patients partner, expanding coverage, embracing prevention and making insurance a tool for everyday health security, not just a crisis shield.

India's health-care system has mastered something that the world is only now beginning to appreciate – delivering quality care at extraordinary scale. Where an MRI in the West may handle seven to eight scans a day, in India the same machine manages many times that volume. This ability to stretch resources without diluting quality is not coincidence. It is the product of decades of ingenuity in doctor-patient ratios, workflow design, and infrastructure use.

The next leap is clear: extend this efficiency to India's vast heartland. Tier-2 and tier-3 cities remain underserved, yet they represent the true



Sangita Reddy

is Joint Managing Director, Apollo Hospitals Group

Health care in India is at an inflection point and must move from being a privilege to becoming every Indian's right frontier. If India can replicate its urban efficiency in these geographies, it will not just close the access gap. It could set a global benchmark for how scale, innovation and inclusion can reshape health care.

Schemes such as Ayushman Bharat (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, or PM-JAY) have redefined access. Covering nearly 500 million people, with ₹5 lakh a family for advanced care, PM-JAY has enabled millions of cashless treatments in both public and private hospitals. Its impact is visible: timely cancer treatments for beneficiaries have increased by nearly 90%.

Expanding private hospital participation in government-backed schemes is essential to reach the next 500 million. But this must be anchored in fair reimbursements and transparent processes, ensuring viability for providers and real value for patients.

Prevention as the most powerful cost-saver A study in Punjab revealed a stark reality – even insured families faced catastrophic expenses on diabetes, hypertension, and other non-communicable disease (NCD) outpatient care. The solution is two-fold: redesign insurance to include outpatient and diagnostics, and launch a nationwide push for prevention. But this is incomplete without public participation.

Alongside payers and providers, people must embrace a preventive mindset – controlling risks, staying alert and raising awareness. Every rupee in healthier lifestyles saves multiples in treatment. If schools, employers, communities and citizens rally behind prevention, India can blunt the looming tsunami of NCDs and secure a healthier future.

India was early to adopt telemedicine and is now pushing boundaries with Artificial Intelligence. Tools that detect early signs of sepsis, triage diagnostic reports, or enable remote consultations are already in practice. These innovations not only improve patient outcomes but also optimise the productivity of doctors and nurses. Digital health is also democratising access. Remote consultations mean that a cardiologist in a metropolitan city can guide treatment for a patient in a village that is hundreds of kilometres away. Combined with the government's Ayushman Bharat Digital Mission, such innovations could enable universal health records and continuity of care across the country.

Regulation and trust as the missing link Health-care innovations are promising, but challenges persist. Insurers in New Delhi are considering a 10%-15% premium hike due to pollution-driven respiratory illnesses which shows how environmental factors raise health-care costs. Without safeguards, such pressures could hit affordability for millions. This is where regulation is crucial. The Finance Ministry has urged the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to strengthen claims of settlement and grievance redress, recognising that trust drives insurance penetration. Without confidence in fair and transparent claims, households will not prioritise health insurance. Robust regulation, paired with fair pricing, is essential to deepen coverage and

In 2023, India's health sector drew \$5.5 billion in private equity and venture capital, fuelling digital health, pharmacy networks, and hospitals. But capital remains skewed toward metros. The true test is directing this to tier-2 and tier-3 cities, building primary networks, and training specialists so that growth translates into inclusion.

build confidence.

India's health care is at an inflection point. Insurance must cover everyday care, providers must scale efficiently, prevention must cut long-term costs, and technology must drive access. With aligned investment and bold public-private partnerships, we can design a system that is not episodic or exclusionary, but universal, resilient, and sustainable. Health care must move from being a privilege to becoming every Indian's right.

### Which sectors are worst hit by tariffs?

How high are the new U.S. tariffs on Indian exports? Which sectors are likely to feel the most pain? What has been the immediate impact on shrimp, textiles, and jewellery? Which sectors are likely to face only a modest impact? What short-term support is the government planning?

EXPLAINER

T.C.A. Sharad Raghavan

#### The story so far:

he 50% tariffs imposed by the U.S. on imports from India came into effect on August 27, sending ripples through the Indian economy and the government. Several sectors, many of them labour-intensive, have the U.S. as a major export destination, and many are already seeing a significant dip in demand. The government is cognisant of this and is devising a plan to support these sectors, at least in the short term.

#### How do we know which sectors will be worst affected?

The intensity of the impact of tariffs can be arrived at by looking at three metrics in combination: the amount exported to the U.S. in absolute terms, the share of the U.S. in that sector's total exports to the world, and the final tariff that sector is facing.

If a sector exports a large amount to the U.S., the U.S. forms a major part of its total exports, and the tariffs are high, then the pain felt by that sector will likely be high. However, if the U.S. forms a small share in a sector's total exports, then the impact is likely to be limited.

#### Which sectors are likely to see a severe impact?

According to data from the Ministry of Commerce and Industry, India exported about \$2.4 billion worth of shrimp to the U.S. in 2024-25, making up 32.4% of its total shrimp exports. Earlier, the U.S. only imposed a 10% countervailing tariff on shrimp from India. However, the addition of the 50% tariff now takes this total to 60%.



Major impact: Several sectors, many of them labour-intensive, have the U.S. as a major export destination, and many are already seeing a significant dip in demand. GETTY INVIGES

Reports indicate that exporter purchase prices of shrimp in Andhra Pradesh – the source of the majority of India's shrimp – fell by about 20% following the 25% tariff imposed on August 7. Prices are likely to fall further due to the current 60% tariff.

India exported \$10 billion worth of diamonds, gold, and jewellery to the U.S. in 2024-25, accounting for 40% of total exports in this sector. Tariffs have now risen from 2.1% to 52.1%. Reports from hubs like Surat already show that production cuts are underway. Surat's diamond polishing industry itself employs about 12 lakh people.

One of the worst-hit sectors is likely to be India's textiles and apparel exports sector. These exports to the U.S. stood at \$10.8 billion in 2024-25, with apparel alone accounting for \$5.4 billion. Further, the U.S. accounts for 35% of India's apparel exports. The sector now faces a 63.9% tariff, up from the previous 13.9%. "Tiruppur exporters are rushing shipments while cancelling new styles," said the Global Trade Research Initiative (GTRI) in its report. "Noida-Gurugram has frozen planned capacity expansions and is considering downsizing, Ludhiana reports a slump in yarn and fabric demand, with working capital under stress, and Bengaluru units are preparing for shift cuts as buyers push for offshore production."

India exported \$1.2 billion worth of carpets to the U.S. in 2024-25, which makes up 58.6% of total carpet exports. Tariffs have increased from 2.9% to 52.9%.

Other significantly affected sectors include handicrafts, leather and shoes, furniture and bedding, and agricultural products such as basmati rice, spices, tea, pulses, and sesame.

#### Which sectors will see a more modest impact?

India's export of organic chemicals to the

U.S. stood at \$2.7 billion. This made up 13.2% of India's total exports. The sector now faces 54% import tariffs, up from the previous 4%. The exporters' body, CHEMEXCIL, and industry bodies have already approached the government for some intervention.

India exported \$4.7 billion worth of steel, aluminium, and copper to the U.S. in 2024-25, about 17% of India's total exports of these metals.

"While the U.S. is not the largest market for Indian metals, it is critical for hundreds of SMEs in the Delhi-NCR engineering belt and eastern foundry hubs," GTRI said.

"The tariff threatens to disrupt jobs in stainless steel, aluminium casting, and copper semi-finished goods, putting severe pressure on small and medium exporters reliant on U.S. orders."

India exported \$6.7 billion worth of machinery and mechanical appliances to the U.S. in 2024-25, making up 20% of its total exports. This sector is also expected to face a drop in demand.

#### Is the government planning to help these sectors?

Prime Minister Narendra Modi and Commerce and Industries Minister Piyush Goyal have been repeating the 'swadeshi' mantra and asking Indians to 'go vocal for local', so that the economy can reduce its dependence on exports. Apart from this, The Hindu reported on August 13 that the government is working on a multi-ministry plan to ease the short-term pain of exporters.

In the medium to long term, the government is working with exporter bodies to diversify their export destinations and make better use of existing free trade agreements. The Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra has also said that the central bank stands ready to provide whatever help it can.

#### THE GIST



Severe impact is expected on shrimp, diamonds and jewellery, textiles and apparel, and carpets due to tariffs rising up to 60%, with reports of production cuts, price falls, and downsizing.



Moderate impact will be felt in organic chemicals, metals, and machinery exports, with SMEs and exporters' bodies seeking intervention.



The government is working on a multi-ministry plan, promoting the 'swadeshi' and 'vocal for local' push, while also aiming to diversify export destinations.

### India braces for impact of 50% U.S. tariffs from today

No comment from Ministry of External Affairs on any goyt, plans for counter-tariffs against the U.S. India has been pushing the Swadeshi mantra and the PM has called on citizens to buy local

While the Indian government is now pushing a Swadeshi mantra to reduce the economy's

55% of U.S.-bound shipments, worth \$47-48 billion, are at a disadvantages of 30% to 35%

#### T.C.A. Sharad Raghavan Suhasini Haidar

NEW DELHI

he United States government is getting ready to implement the 25% additional tariffs imposed on India by U.S. President Donald Trump, which come into effect on Wednesday. On Tuesday, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) uploaded a notification of the new tariffs to be published in the official register the following day.

The Indian government is pushing a Swadeshi mantra to reduce the economy's reliance on exports, with Prime Minister Narendra Modi on Tuesday calling upon Indians to be "vocal for local" and buy Indian goods. Indian exporters, however, are bracing themselves for a sharp fall in business to the U.S., with early estimates predicting that more than \$47 billion worth of goods will face the 50% tariff rate. This includes the 25% tariff that Indian imports have attracted since August 7 plus an additional 25% tariff imposed as a penalty for India's import of oil from Russia.

#### Exemptions given

This additional tariff will not apply to iron, steel, or aluminium products; passenger vehicles such as sedans, sport utility vehicles, crossover utility vehicles, minivans, cargo vans, and light trucks; semi-finished copper, and intensive copper derivative products, among others.

The Ministry of External Affairs did not comment on whether India is planning any counter-measures

#### reliance on exports, Indian exporters are bracing themselves for a sharp fall in business with the United States of America

**Tariff travails** 

Market loss: 55% of Indian exports rendered uncompetitive compared to neighbouring countries, warns FIEO

Sectors to be hit: Apparel, textiles, gems and jewellery, shrimp, carpets, and furniture

Extent of impact: Imports from these sectors could plunge 70%

- India stands by its statement that these tariffs are 'unreasonable'
- PM Narendra Modi to meet Chinese President Xi Jinping on August 30

or counter-tariffs against the United States, though a senior official said that India stands by the MEA's earlier statement calling the sanctions "unfair, unjustified and unreasonable".

The U.S. DHS notification detailed the implementation of Mr. Trump's executive order.

"To effectuate the President's Executive Order 14329 of August 6, 2025... which imposed a specified rate of duty on imports of articles that are products of India, the Secretary of Homeland Security has determined that appropriate action is needed to modify the Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) as set out in the Annex to this notice," the notice said.

"The duties set out in

the Annex to this document are effective with respect to products of India that are entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption, on or after 12:01 a.m. eastern daylight time on August 27, 2025," it added.

The MEA did not comment on whether the additional tariffs will be on the agenda when Prime Minister Modi meets Chinese President Xi Jinping in Tianjin on August 30. Last week, the Chinese Ambassador to India had referred to the U.S. as a "bully", saying the Chinese government opposes the tariffs and "firmly stands with India" on the issue.

Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra, too, said the central bank "would not be found wanting" in supporting those sectors that will be adversely affected by the tariffs.

The Goods and Services
Tax (GST) Council is all set
to meet on September 3 to
4 to decide on a slew of
rate cuts and rationalisation measures suggested
by the Union government
to not only ease the overall
tax rate borne by consumers, but also simplify the
indirect tax regime.

This consumption boost

is expected to mitigate some of the slowdown in economic growth that higher tariffs could cause.

#### Worried exporters

Indian exporter bodies and trade experts, however, are projecting a substantial hit to India's exports.

According to the Federation of Indian Export Organisations president S.C. Ralhan, the development could "severely impact" India's exports to the U.S., "with approximately 55% of India's U.S.-bound shipments (worth \$47-48 billion) now exposed to pricing disadvantages of 30% to 35%, rendering them uncompetitive in comparison to competitors from China, Vietnavn, Cambodia, Philippines, and other Southeast and South Asian countries".



#### **GETTY IMAGES**

### With Sci-Hub gone, will the 'One Nation, One Subscription' scheme step up?

Internationally, publishers such as Elsevier and Wiley have used the courtroom to buttress the legitimacy of their business model and portray shadow libraries like Alexandra Elbakyan's Sci-Hub as rogue actors rather than as symptoms of dysfunction

Vasudevan Mukunth

hen the Delhi High Court ordered internet service providers to block access to Sci-Hub and its mirrors, it closed a chapter in one of the more fraught debates in contemporary research: who gets to read research papers, and who must pay. The verdict followed years of litigation by Elsevier, Wiley, and the American Chemical Society against Sci-Hub founder Alexandra Elbakyan. The court held that Ms. Elbakyan had violated an undertaking not to upload publishers' articles, and that Sci-Net, a mirror service, was being used to circumvent judicial orders, leaving her prima facie in contempt.

This seemingly straightforward case of copyright violation – private corporations defending intellectual property against piracy – is transformed by its context. The publishers' legal win must be weighed against the case for public access to knowledge, the economics of scholarly publishing, and the arrival of 'One Nation, One Subscription' (ONOS), which together suggest that depending on courtroom battles might be misplaced.

#### An endeavour apart

Scientific publishing is unlike other enterprises where piracy drains income from creators. Scientists who produce and review research are not paid by journals: their work is largely funded by public money in India. Yet publishers charge institutions exorbitant subscription fees, sometimes lakhs of rupees per journal. Publishers have defended these figures on grounds of quality control and peer review. But with profit margins of 30% or more and a voluntary review system, the system has often resembled rent-seeking.

On the other hand, Sci-Hub was always vulnerable to the charge of copyright infringement. Courts in the U.S. and Europe have consistently ruled against it, and now the Delhi High Court has joined that chorus. While this is uncontroversial from a strictly legal standpoint, the larger implication is troubling. The judgment risks reinforcing the idea that legal strategies to restrict access are valid even in settings where no affordable or equitable alternative exists.

Internationally, publishers have used the courtroom to buttress the legitimacy of their business model and portray shadow libraries like Sci-Hub as rogue actors rather than as symptoms of dysfunction. In fact, the outcome in the High Court fits a pattern: publishers protect a lucrative business model, courts apply the letter of the law, and the underlying lack of access stays unresolved. Experts have been steadfast that the dysfunction is the real disease that needs to be cured.

#### Unified subscription

The Indian government recently put forward the ONOS initiative as an alternative. Whether it succeeds will determine if future generations of researchers must still look for back doors. The Union Cabinet approved ONOS in 2024 with an outlay of ₹6,000 crore for its first phase (2023-2026). Under the scheme, the state has negotiated a bulk subscription with 30 major publishers so that research institutions − all public and, in phase II, many private ones − have equal access to some 13,000 journals.

Thanks to the rise of preprints and institutional repositories, more than half of the scientific papers worldwide are now open access. From 2026, all federally funded research in the U.S. must be openly accessible; the EU's Horizon Europe programme has similar requirements. Paying crores for subscriptions at a time when openness is expanding could render ONOS an

expensive detour. Until phase II, independent researchers and those at private institutes and centres – who may outnumber their counterparts at public centres – will still have to pay considerable non-ONOS fees to access journals and still depend on platforms like

ONOS also doesn't address structural flaws in scholarly publishing, reinforces dependence on foreign publishers, and continues to force Indian researchers to transfer copyrights of their own work to journals. At the same time, the subscription model that ONOS pays for still encompasses several thousand journals, including those that many researchers wish to be published in. Blaming ONOS on this count rather than a long-awaited culture change, especially not one the state could have forced, wouldn't make sense.

Ms. Elbakyan's attempts to (further) incentivise scholars to contribute to Sci-Hub's collection of papers using the Sci-Net portal and its cryptocurrency-based rewards system also don't seem to be succeeding. Whatever moral force Ms. Elbakyan's project once had has since been squandered by technical unreliability and increasing redundancy. The High Court's injunction may thus be decisive less because of its punitive sting than because of the fact that the Indian community is already moving on.

#### Pathology of publishing

At the time the publishers sued Ms. Elbakyan in 2020, there was no realistic prospect of universal access. For countless researchers outside elite institutions, Sci-Hub was (and remains) often the only path to knowledge. Both legal experts and researchers have thus contended that on principle alone, courts could have acknowledged the unique nature of scientific publishing – that the

absence of author royalties, prevalence of public funding, and exorbitant pricing by publishers set it apart from creative industries like music or film – and refused to privilege corporate margins over public good.

Today, ONOS provides a legal path to broader access and its success could render shadow libraries unnecessary. It needs to prove it can seamlessly deliver equitable access at a fair cost while India must foster greater indigenous publishing capacity. On both counts, however, it's not clear if ONOS can do so in its present form. For example, on the first count, the concerned authorities will have to improve the efficiency of use by regularly consulting researchers on which journals are useful and keep other options, like a per-article fee for esoteric journals, open.

On the second, ONOS frees funds at many individual institutes and the scheme currently intends to redirect them towards pay-to-publish (rather than pay-to-read) open-access journals. Instead, governments may consider using them to install and manage institutional repositories. Experts have said this service could in turn be complemented by a national rights retention policy, like those at Harvard University and MIT, that require researchers to deposit their work in the repositories regardless of publishers' restrictions.

This could keep researchers in control of their work, force pay-to-publish journals to modify their terms, and allow people who aren't linked to university and/or public libraries to access papers, including journalists, activists, and independent researchers.

Sci-Hub in many respects remains a symbol of resistance against publishers' profiteering. Following the Delhi High Court order, the question is whether ONOS will step up to eradicate the disease rather than simply manage the symptoms.

# 98.2% of Bihar's electors have submitted documents, says EC

Remaining 1.8% have eight days to submit documents, and rectify mistakes in the draft rolls, the poll body said; officers will complete verification of 'eligibility documents' by September 25, the EC added; final rolls will be published on September 30

#### The Hindu Bureau

NEW DELHI

he Election Commission said on Sunday that the special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bihar was on schedule even as the Opposition intensified protests against it.

The EC said it had received documents from 98.2% of the 7.24 crore electors in the State in 60 days.

The remaining 1.8% voters had eight days to submit requisite documents that were not provided during enumeration, and to rectify mistakes on the draft electoral rolls published on August 1.

The EC said that 1.64% of the electors submitted documents per day.

#### Status update

The Election Commission on Sunday said that the special intensive revision (SIR) of electoral rolls in Bihar is on schedule

- From June 24 to August 24, 98.2% of the electors submitted their documents
- On an average, the EC received documents from about 1.64% electors per day
- Electoral registration officers will take a final call on the claims and objections received
- The final electoral roll will be published on September 30



Ground zero: Officers collecting forms from electors in Vaishali district of Bihar during the first phase of the SIR. ANI

The poll body said that the electoral registration officers (ERO) and the assistant electoral registration officers (AERO) would take a final call on the claims and objections received, and they would complete the verification of "eligibility documents" by September 25. The final electoral rolls will be published on September 30, it added in a statement.

The SIR was done between June 24 and July 25. Claims and objections along with documents can be submitted till September 1.

The poll panel appreciated the efforts by the Chief Electoral Officer of Bihar, District Election Officers of all 38 districts, 243 EROs, 2,976 AEROs, 90,712 booth-level officers, lakhs of volunteers and field representatives of all the 12 major political parties, and their 1.6 lakh booth-level agents.

#### 'Docs being collected'

"The exercise to collect their documents with the help of BLOs and volunteers is going on. Thus, just like collection of enumeration forms, work related to collection of documents is also likely to be completed before time," the release said, adding that verification of documents is also being done concurrently by the EROs and the AEROS.

The Election Commission also said that out of 7.24 crore electors in the draft rolls, only 0.16% of the voters have filed claims and objections so far.

"10 from the BLAs of 12 recognised political parties in Bihar, NIL by persons who are not electors of that Assembly Constituency and 1,21,143 by electors within their Assembly Constituency," the press note added.

### Is India underestimating the cost of dealing with invasive species?

In a new assessment, non-native plants have emerged as the most economically impactful invasive species worldwide as well as the costliest group vis-à-vis the cost of management, demanding \$926 billion in 1960-2022; next in line were arthropods (\$830 billion) and mammals (\$263 billion)

Monika Mondal

amage from non-native plants and animals expanding into new ecosystems has cost society more than \$2.2 trillion worldwide, a new study by an international team of researchers has

Published in Nature Ecology & Evolution, the study used numbers from InvaCost, a public database that records the economic costs of biological invasions by country, and modelling exercises to analyse data from 1960. It concluded that costs may have been underestimated by 16x over previous estimates

Beyond global economic losses, the study also modelled the impact in 78 countries for which no data was previously available. In India. a nation grappling with numerous environmental and economic challenges, the findings underscore an oft-overlooked financial

A global discrepancy Europe was found to have the highest potential impact in absolute terms at \$1.5 trillion (71.45% of global cost), followed by North America (\$226 billion), Asia (\$182 billion), Africa (\$127 billion), and Australia and Oceania (\$27 billion).

Brian Leung, one of the lead researchers and the UNESCO Chair for Dialogues on Sustainability, said, "The cost of invasions might just be higher because of the cost of things in Europe. There's more to damage, the cost of the agricultural products, and the cost of management might be higher."

The study did not estimate a total economic damage figure for India in absolute terms but emphasised the magnitude of underreported management costs. In fact, among all the countries assessed, the study found India had the highest percentage discrepancy of management expenditure: 1.16 billion percent.

Per the study, this exceptionally high disparity suggests a significant amount of management spending in India has likely been unrecorded or underreported in the existing data, leading to a substantial "hidden" cost. The researchers were careful to note that India's limited resources could have contributed as much to this gap as a recording bias in the InvaCost database, which may be overlooking reports in languages predominant in Africa and Asia.

Europe reported a discrepancy of 15,044%, followed by Asia (3,090%), and Africa (1,944%). The median cost discrepancy among the assessed countries was 3,241%.

Mr. Leung said he was unsure of



A large portion of Bandipur National Park is covered by the lantana weed, which is highly combustible when dry, FILE PHOTO

India-level specifics or how the figures break down, but noted that general management strategies could include different elements like prevention, eradication, control or suppression, and efforts to slow the spread of invasion. "These are all tools used for managing invasions," he said.

S. Sandilyan, a former fellow on Invasive Alien Species at the Centre for Biodiversity Policy and Law in Chennai, said the findings of the study are plausible. "India is falling short in documenting, reporting, and strategically funding biological invasion management. Lack of centralised data systems, limited inter-agency coordination, and competing conservation priorities exacerbate this,"

#### Who are the invaders?

Plants emerged as the most economically impactful invasive species worldwide as well as the costliest group vis-à-vis the cost of management, demanding \$926.38 billion in 1960-2022. Next in line were the arthropods (\$830.29 billion) and mammals (\$263.35 billion). The researchers speculated that these species spread to new ecosystems - where they could thrive at the cost of its incumbents primarily through trade and travel, helped along by globalisation and bilateral deals. They singled out Japane knotweed (Reynoutria japonica) and common lantana (Lantana camara) to be among the costliest to manage per square

Leung, however, cautioned that simply eradicating all invasive species would make the problem worse. "A lot of the agricultural products that dominate our system now are not native," he said.



India is falling short in documenting. reporting, and funding invasion management, Lack of centralised data systems, limited coordination, and competing conservation priorities exacerbate this

S. SANDILYAN
CENTRE FOR BIODIVERSITY POLICY AND LAW IN CHENNAI

"Invasive species transport is a byproduct of trade and importation of living organisms because we want them, and sometimes these are the driving forces behind invasions," Mr. Leung added. "Europe has been doing that for a long time."

This presents a two-faceted challenge: on one hand, there is an imperative to mitigate economic losses; on the other, there is the desire to foster further globalisation. Thus, according to Mr. Leung, efforts must simultaneously be made to curtail the spread of invasive species and address global warming by increasing vegetation. Given these complex, intersecting objectives. reconciling these disparate goals in studying invasive species becomes a significant challenge, he added.

The study also acknowledged that several international policies to deal with invasive species are in place, which scientists at large believe have had a positive effect on reducing the rate of biological invasions. Key among them is a regulation concerning shipping traffic and trade

practice: the International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments (a.k.a. Ballast Water Management Convention), which is designed to prevent the spread of harmful aquatic organisms from one region to another via ships' ballast water

Likewise, regulations under the Convention on Biological Diversity call on parties (including India) to "prevent the introduction of, control, or eradicate those alien species which threaten ecosystems, habitats, or species.

These international agreements underscore a global recognition of the threat posed by invasive species and efforts to mitigate their spread through various control points.

As for management costs, Mr. Leung said response strategies can range from preventing new invasions aiming for complete eradication of established populations or controlling their spread to minimise impact.

The large discrepancies in reported costs also underscore the need for improved data collection, comprehensive tracking of expenditures, and robust reporting mechanisms.

For example, even though the cost estimates in Africa are really quite limited, it doesn't mean the damages are limited," he explained.

While the study does not say anything about the state of invasive species, it may be a call to action. Its specific analysis and the database were based on the measured economic costs, according to Mr. Leung, "because it's often easier to measure and people often understand money better." (Monika Mondal is a freelance science

and environment journalist. a.monikamondal@gmail.com)

#### THE GIST

Europe was found to have the highest potential impact in absolute terms at \$1.5 trillion, followed by North America (\$226 billion), Asia (\$182 billion), Africa (\$127 billion), and Australia and Oceania

India had the highest percentage discrepancy of management expenditure: 1.16 billion percent. This suggests spending has likely been unrecorded or underreported, leading to a substantial hidden cost. Europe reported a discrepancy of 15,044%, Asia (3,090%), and Africa (1,944%)

Researchers cautioned that simply eradicating all invasive species would make the problem worse since many agricultural products acro the world are not native. Invasive species are a byproduct of trade and importation of living

### The new Constitution Bill, the need for a balancing act

oral integrity in the political class is a paradox that India has continually struggled with. While, on the one hand, the electorate demands moral rectitude in the political class, there has, on the other, been a pervading spectre of criminality prevailing in the political class. The proposed Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, that was introduced in the Lok Sabha on August 20, 2025, is aimed at filling this vacuum by providing a condition. Under this, Ministers, Chief Ministers and even the Prime Minister must either resign or automatically be subject to removal if they continue to be in custody even after a consecutive period of 30 days in crimes that carry a maximum punishment of five years or more of imprisonment.

On the surface, the action appears to be a decisive initiative toward enabling cleaner politics. It touches upon the disturbing fact of corrupt leaders in custody holding on to power, a situation that has made people lose trust in governance. But there are political pitfalls and constitutional quandaries that lurk beneath its promise.

The foundation for this Bill rests on Articles 75, 164 and 239AA of the Constitution, which deal with the appointment and tenure of Ministers in the Union, States and Delhi, respectively. While Articles 75(I), 164(I) and 239AA(5) mandate that Ministers shall hold office at the pleasure of the President of India (or Governor), this "pleasure" has been judicially interpreted within the bounds of constitutional morality and legal propriety, as in cases such as Shamsher Singh and Anr. vs State Of Punjab and Nabam Rebia And Etc. Etc. vs Deputy Speaker And Ors.

#### Judicial pronouncements

The Supreme Court of India, in S.R. Bommai vs Union of India, underscored the role of constitutional morality as a guiding principle, thus pronouncing that democratic institutions must be nurtured through integrity and accountability. Later, in Manoj Narula vs Union of India, the Court directly addressed the ethical dimension of ministerial appointments, warning that individuals with serious criminal charges should not be entrusted with executive power. Although the Court stopped short of mandating automatic removal, it clearly signalled that morality is intrinsic to the constitutional framework. The Bill, therefore, draws strength from these pronouncements, seeking to give legislative form to what has long been a judicially recognised moral imperative.

But this Bill's very ambition may be its Achilles' heel. The most glaring issue concerns the principle of presumption of innocence, which forms part of the right to life and liberty under Article 21. To equate arrest and detention with



Samayeta Bal

is an advocate, a former Legislative Assistants to Members of Parliament (LAMP) Fellow (2024-25), and, currently, a Parliamentary, Legislative and Policy Researcher

The Joint

Committee

needs to

carefully

Parliamentary

recalibrate the

formulation of

(One Hundred

and Thirtieth

Amendment)

Bill, 2025

the Constitution

grounds for removal, without conviction or even the framing of charges, risks undermining this foundational constitutional value, Section 8(3) of the Representation of The People Act concerns the disqualification of members on the conviction of certain offences. In the case of Lily Thomas vs Union of India, the Supreme Court held that a lawmaker, only upon conviction, immediately stands immediately disqualified. The three-month window to file an appeal and continue as a legislator was also struck down, thus providing jurisprudential support for stringent accountability even before the existence of the Bill. Here, it is important to note that disqualification begins only when someone is convicted, and not when someone is arrested or

The problem is compounded by the Bill's reliance on executive discretion through the insertion of Clause 5A after Clause 5 of Article 75, Clause 4A after Clause 4 of Article 164 and Clause 5A after Clause 5 of Article 239AA of the Constitution. Ministers can be removed on the advice of the Prime Minister or Chief Minister, but automatic removal kicks in if such advice is withheld. This dual mechanism politicises the process: a Prime Minister may shield allies for 30 days, while a hostile Chief Minister may allow rivals to fall by the automatic rule. Instead of insulating governance from partisanship, the Bill risks embedding accountability in the shifting sands of political calculation.

#### Inconsistency in treatment

The inconsistency in treatment between legislators and Ministers further complicates matters. Members of Parliament and Members of State legislatures face disqualification only upon conviction under the Representation of the People Act. By contrast, Ministers under this Bill would be forced to resign on mere detention. This creates a paradoxical situation wherein a legislator convicted of corruption may technically continue as a Minister until disqualified under the Act, while a Minister only under arrest would be forced out. The asymmetry may appear to elevate the standards for executive office, but it also undermines consistency in the constitutional treatment of public officials. It risks deterring capable individuals from accepting ministerial responsibility, knowing that they face harsher consequences than their legislative peers on the basis of unproven allegations.

There is also the problem of the "revolving door". Because the Bill allows reappointment once a Minister is released from custody, there could be cycles of resignation and reinstatement depending on the pace of legal proceedings. Imagine a Chief Minister who is arrested and detained for 31 days, who is forced to resign, but later released on bail and promptly reinstated by the Governor. The State would have endured

weeks of political uncertainty with little to gain in ethical accountability. Such instability may not only weaken governance but also incentivise tactical legal manoeuvres, where political actors use the law as a tool to manipulate executive offices.

#### Need for a more nuanced model

None of this is to deny the urgency of reform. The rise of criminalisation in politics is a stark reality. According to a comprehensive analysis by the Association for Democratic Reforms and National Election Watch of all 543 winning candidates in the 2024 general election, 251 Members of Parliament (46%) had declared criminal cases against themselves, up from 43% in 2019, 34% in 2014, and 30% in 2009, representing a 55% increase over 15 years. Yet, the bluntness of its approach risks undermining both the principle of fairness and the stability of governance. A more nuanced model would better serve the constitutional goal of clean politics without eroding democratic safeguards.

One pathway could be to link removal not to arrest but, instead, to judicial milestones such as the framing of charges by a competent court. This would ensure that only cases that pass initial judicial scrutiny trigger resignation, filtering out frivolous or politically motivated arrests. Another safeguard could be the establishment of an independent review mechanism, such as a tribunal or a judicial panel, to examine whether the conditions for removal have been met. This would prevent executive overreach and ensure impartial application. Similarly, instead of outright removal, the law could provide for interim suspension of ministerial functions during ongoing trials, allowing governance to continue without compromising accountability. Most importantly, the Bill should refine its scope to apply only to offences involving moral turpitude and corruption, rather than casting a wide net over any offence punishable with five years' imprisonment, which could include relatively minor criminal conduct.

In sum, the Constitution (One Hundred and Thirtieth Amendment) Bill, 2025, stakes out a significant normative position that citizens might welcome as a forceful stand against corruption and criminality. But its formulation elides the inherent tension between safeguarding democratic deliverance of justice and urgent demands for ethical governance. Unless the Joint Parliamentary Committee (JPC) carefully recalibrates to incorporate due process and institutional checks - the Bill is with the JPC - it could transmute constitutional safeguards into instruments of political exclusion, testing the delicate balance of India's democratic experiment. For, in the long run, power without integrity corrodes democracy, and integrity without fairness endangers it.



REUTERS

## Trump's Intel deal: how the U.S. is reinventing state capitalism

Washington's deal to take a nearly 10% stake in Intel is more than just a bailout for the struggling chipmaker; it is a striking symbol of a new era in American economic policy, one that bears an uncomfortable resemblance to European state capitalism of the 1960s

John Xavier

or decades, U.S. politicians have looked across the Atlantic at Europe's experiments with state-directed industry with a mixture of pity and scorn. The French model of dirigisme, with its state-owned champions and politically guided investments, was often held up as a cautionary tale of bureaucratic meddling and economic sclerosis.

Yet, in a move that turns decades of free-market economics on its head, the U.S. government is now a leading shareholder in one of Silicon Valley's founding giants. The agreement for Washington to take a nearly 10% stake in Intel is more than just a bailout for a struggling chipmaker; it is a striking symbol of a new era in American economic policy, one that bears an uncomfortable resemblance to the European state capitalism of the 1960s.

#### Uneasy alliances

The deal itself, announced by President Donald Trump, is an extraordinary piece of political theatre and financial engineering. The 10% stake in Intel will not be funded by new money, but through a clever conversion of funds already allocated to the chipmaker through the 2022 CHIPS and Science Act, which was designed to bolster domestic semiconductor manufacturing.

The current arrangement with Intel was born of a hurried rapprochement between the President and Intel's chief executive, Lip-Bu Tan. Mr. Trump had previously called for Mr. Tan's resignation over his prior investments in Chinese start-ups. After a meeting, however, the President's tone changed dramatically. It is a transactional, almost improvisational, approach to industrial strategy that has become a hallmark of the administration.

"I said, I think you should pay us 10% of your company. And they said 'yes' – that is about \$10 billion," Mr. Trump told about his interaction with Intel during an Oval Office press briefing on Friday. "He walked in wanting to keep his job, and he ended up giving us \$10 billion for the U.S.," Mr. Trump said.

This is not Mr. Trump's isolated venture. The White House has struck other unusual deals, including allowing Nvidia and AMD to sell certain AI processors to China on the condition that Washington receives a portion of the revenue. The Intel deal, however, marks the most significant direct equity stake in a major technology firm, prompting Mr. Trump to declare, "We do a lot of deals like that: I'll do more of them."

The parallel with 1960s Europe is compelling. Back then, governments in countries like France and Britain, alarmed by what was dubbed the "technology gap" with America, poured public money into creating "national champions" in strategic sectors such as computers and aerospace. The belief was that only the state had the deep pockets and long-term vision to build companies that could compete on a global scale. These policies, however, were largely unsuccessful, often resulting in uncompetitive, state-coddled firms that

drained taxpayer funds and lagged in innovation.

Intel, once the undisputed king of semiconductors, now finds itself in a position that makes it a candidate for such state intervention. The company has been haemorrhaging money, posting a staggering operating loss in 2024, and has fallen technologically behind rivals like Taiwan's TSMC. Its struggles to attract external customers for its manufacturing arm, and delays in construction plans in States like Ohio have cast doubt on its turnaround strategy. This weakness made Intel uniquely receptive to Washington's offer. Foreign competitors like TSMC and Samsung, which are also building factories in the U.S. with CHIPS Act subsidies, are far too successful and valuable to entertain ceding a significant equity stake to Uncle Sam.

So, this is not a case of the government picking a winner, but of preventing a national icon – and a critical node in the domestic semiconductor supply chain – from falling further into irrelevance.

#### A new kind of state intervention

However, there is a crucial distinction between this new American interventionism and its European precursor. The government's investment is structured as a passive, non-voting ownership stake. Washington will have no seat on the board and no formal governance rights, and has agreed to vote with the company's board on most shareholder matters.

This suggests a more sophisticated model than the heavy-handed state control of the past. The goal appears to be to provide vital capital and a government seal of approval, ensuring the taxpayer shares in any potential upside from a successful turnaround, without succumbing to the temptation of political meddling in day-to-day operations.

Nonetheless, the risks are profound. The line between a passive partner and an influential stakeholder can blur, especially if Intel's troubles persist. Future administrations may not share the current hands-off approach. The government is now financially exposed to Intel's performance, creating a dangerous precedent where corporate failures in strategic sectors become direct liabilities for the public purse. This move fundamentally alters the relationship between the state and private enterprise in a way that could introduce new and unpredictable forms of political and market risk.

The U.S.'s foray into shareholder activism is a reluctant one, born not of ideological conviction but of geopolitical necessity and fierce technological rivalry with China. The long-held belief in the inherent superiority of the free market is giving way to a pragmatic, if uneasy, embrace of industrial policy.

The Intel stake is a bold experiment in this new reality. The critical question is whether the U.S. can learn from Europe's past, deploying the power of the state to nurture a strategic industry without smothering the competitive spirit that made it a world leader in the first place. The American taxpayer now has \$10 billion riding on the answer.